

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER: The Minister has stated that these welfare centres would be in the nature of recreation centres for agricultural labour. As he is aware, in West Bengal the agricultural labour is not getting the minimum wage. What machinery has the Government got to see that the agricultural labour is guaranteed the minimum wage in West Bengal?

SHRI RAGHUNATHA REDDY: The implementation of the minimum wage under the Minimum Wages Act comes within the purview of the State Government. In view of the decision taken by the Labour Ministers' Conference, various State Governments have been persuaded to revise their minimum wages and steps are being taken very vigorously to pursue the same.

Development of Villages surrounding Public Sector Steel Plants

*316. **SHRI K. M. MADHUKAR** Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) whether some measures are proposed to be taken by the public sector steel plants for development of villages surrounding them; and

(b) if so, the broad outlines thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL AND MINES (SHRI SUKHDEV PRASAD) (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b). The Memorandum of Agreement reached by the Joint Negotiating Committee for the Steel Industry on 30th July, 1975, provides, among other things, that in view of the fact that it has not been possible to provide housing facility to all the employees of the companies and a number of such employees live in bustees and communities around the steel plants, wherever such communities are located in the company

area, every effort will be made to improve facilities such as provision of roads, electricity, drinking water, sanitation and public telephone booths in such bustees and communities, and some funds will be set aside for this purpose every year. The public sector steel plants also have under their consideration, on an experimental basis, some proposals for the socio-economic development of some peripheral villages subject to the availability of funds and other resources.

श्री कमला मिश्र "मधुकर" : यह बात जान कर बहुत खुशी हुई है कि इस्पात मंत्रालय ने इस बात को कबूल किया है कि राजकीय क्षेत्र में जो चार इस्पात के कारखाने हैं उनके अगल बगल की वस्तुओं के विकास की आवश्यकता है, इस को आप ने महसूस किया है। तो मैं जानना चाहता हू कि झिलाई, रकेला, बोहारो और दुर्गापुर इन तमाम इस्पात के कारखानों के अगल बगल के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए कोई समग्र योजना बनाई गई है और उस का मूल्यांकन किया गया है कि उस में कितना धन खर्च होगा? उसकी पूरी तफवील कब तक पूरी हो जायेगी? इन क्षेत्रों के विकास के लिए कोई योजना बनाई गई है या यों ही चलने वाला स्वाभाविक विकास हो रहा है? मैं जानना चाहता हू इन के विकास के लिए कोई योजनाबद्ध योजना है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : श्रीमन्, क्याल इस बात का है कि बहुत से हमारे जो इस्पात के कारखाने हैं उन के अन्दर बहुत से ऐसे हमारे श्रमिक हैं जो आस पास के गांवों से आते हैं। बहुत से ऐसे भी श्रमिक हैं जिन को अभी तक हम मकान नहीं दे पाए हैं। तो ऐसे मजदूर जो आस पास की बस्तियों में रहते हैं और वहाँ अन्दर सड़क

की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, या पक्काई लिखाई और दबा की सुविधा नहीं है तो उन बस्तियों का भी इस तरह से विकास करें कि हमारे श्रमिकों को जो वहां से आते हैं किसी तरह की असुविधा न हो। मुख्य मकसद इस का यह है और इसी ब्याल से यह कहा गया है अपने कारखानों को कि वह स बात को देखें कि जो उनके आस पास के गांव हैं उन के विकाम के लिए वे क्या कर सकते हैं, कुछ पैसा उस के लिए लगा सकते हैं तो लगाना चाहिए। इस का अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि इस्पात के कारखानों के आस पास के विकास की जिम्मेदारी वह अपने ऊपर लेगे, यह मुख्य प से हमारा काम नहीं है लेकिन फिर भी अपने सामाजिक दायित्व को ध्यान में रखते हुए जहा कारखाने के आस पास वह कुछ कर सकते हैं वहा की सुविधा बढ़ाने के लिए तो वह उन को जरूर करना चाहिए। इसी दृष्टि से रुरकेला के आस पास के गांवों के इस तरह के विकास के लिए अनुमानतः 47 लाख 80 हजार की योजना स्वीकृत हुई थी जिस में से यह तय हुआ था कि 10 लाख पया तो फौरन कारखाना देगा और फिर कोशिश करेंगे कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से तथा स्थानीय प्रशासन के सहयोग से हम इस काम को करें। स प्रकार का निर्देशन दिया गया है लेकिन माननीय सदस्य को यह बात नहीं समझ लेनी चाहिए कि तमाम आस पास के इलाके के विकास की जिम्मेदारी हमने ले ली है बल्कि मुख्य प से जहां श्रमिक रहते हैं वहां पर जो कुछ हो सकता है वह करेंगे।

श्री कमला जिब 'बबुकर' : जब आपने इस बात को कबूल किया है कि इस्पात मंत्रालय आस पास के गांवों का विकास करना चाहता है तो उस विकास योजना के अन्तर्गत क्या कोई ऐसी योजना है जिसके जरिए अगल बगल के गांवों में छोटे मोटे उद्योग-धंधों का विकास हो सके और जो वहां पर वाई प्रोडक्ट निकलते हैं उनसे सम्बन्धित उद्योग-धंधों का विकास हो सके ?

श्री चन्द्रजीत थाबब : इस्पात कारखानों के प्रबन्धकों का यह काम नहीं है कि वहां पर छोटे मोटे उद्योग-धंधे विकसित करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लें लेकिन जो कारखानों से इस्पात का प्रोडक्शन होता है उसके सम्बन्ध में अगर कोई इंडस्ट्रीज लगाते हैं उनको सुविधा मिल सके, उनको कोई दिक्कत न हो, इसके लिए जो सहयोग हमारी तरफ से दिया जा सकता है वह दिया जायेगा।

श्री मान सिंह भौरा : जहां तक मजदूरों को हाउसिंग फ़ैमिलीज देने का सवाल है, एक बात हमारी नोटिस में हर जगह आती है कि शेड्युल्ड कास्ट्स और शेड्युल्ड ट्राइब्स के जो लोग होने हैं उनको किराये पर भी कोई मकान नहीं देता तो क्या मन्त्री जी इस बात को ध्यान में रखेंगे कि पहले शेड्युल्ड कास्ट्स और शेड्युल्ड ट्राइब्स के जो एम्प्लॉईज हैं उनको रहने के लिए जगह दी जाये ?

श्री चन्द्रजीत थाबब : जहा तक हाउस एलाटमेंट का सवाल है अपने ट्रेड यूनियनों के नुमाइन्दों के साथ बैठकर कुछ नियम बनाए हैं और जो हम आगे करना चाहते हैं उस पर उनके साथ बैठकर विचार करते हैं और हमारे

यह निर्देश है कि बीकरी में और इस तरह के दूसरे कामों में जो निर्बल वर्ग के लोग हैं, सेच्युल्ड कास्ट्स और सेड्युल्ड ट्राइब्स के उनको मूल्यांकन दी जाये लेकिन कमी कमी जो दूसरे लोग पहले से काम कर रहे उनको नहीं मिलता है तो कठिनाई आती है फिर भी इन बातों का ध्यान आम तौर पर रखा जाता है।

Extension of Employees' State Insurance Scheme to Labourers

*317. SHRI S. M. BANERJEE: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether coverage under the Employees' State Insurance Scheme has steadily expanded; and

(b) whether Government propose to extend the E.S.I. Scheme to unorganised working population such as agricultural labourers, bidi workers, contract labourers, construction workers?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI RAGHUNATHA REDDY): (a) Yes, Sir.

(b) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(b) The Employees' State Insurance Corporation has furnished the following information:—

The agricultural workers employed in workshops in agricultural farms and the contract labour employed in connection with the work of factories/establishments to which the Employees State Insurance Oct, 1948 already applies and which are situated in the areas where the benefit provisions of the Act are in force, are already coverable under the E.S.I. Scheme. Further, such of the bidi workers as are employed in non-power using

factories/establishments and shops, employing 20 or more persons and located in the areas where the benefit provisions of the Act are in force, will also be coverable under the Scheme as and when the provisions of the Act are extended to these classes of establishment by the State Governments under section 1(5) of the E.S.I. Act. The extension of the Scheme to the other categories of workers in the unorganised and semi-organised sectors of employment, including agricultural labourers, construction workers etc., is not considered feasible for the present, in as much as the organising of medical and other facilities for such workers will present serious difficulties.

SHRI S M BANERJEE: I would like to know whether it is a fact that the ESI scheme has not been extended to even 50 per cent of the workers working in the organised sector and if so, whether there is a plan to extend it further during the Fifth Plan, and if so, the number of workers likely to be covered and whether construction workers will also be covered.

SHRI RAGHUNATHA REDDY: The ESI scheme is being extended from time to time having regard to the ability of the organisation to deal with the matter and also the industrial organisations to be covered. For the information of the hon Member I may state that after the recent amendment of the Act raising the remuneration of the workers to be covered from Rs. 500 to Rs 1,000, this sector alone consists of nearly 51 lakhs of additional workers, and the total number so far covered is 56 lakhs. In fact, there is an increase of six lakhs workers as a result of this, and the total beneficiaries come to nearly 2.2 crores in India, including the members of the workers' families. The scheme is in operation in three central industries, in 15 States and in the Union Territories of Delhi and Pondicherry. We are trying our best to cover as many workers as